कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

एनडीए रैली – बांका........ 6
मुंगेर........ 7
जनसभा, कोल्लम (केरल)........ 8

सरकार की उपलब्धियां

मुद्रा योजना का उद्देश्य कमजोर उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना.. 9
लागू हुआ काला धन कानून........ 10
विदेशी निवेश में भारत है नंबर वन........ 11

वैचारिकी

जीवन का ध्येय
पं. दीनदयाल उपाध्याय........ 12

श्रद्धांजलि

प्रो. राम कापसे नहीं रहे........ 14

बिहार विधानसभा चुनावों पर विशेष

अध्यक्षीय प्रवास : बेगूसराय, औरंगाबाद........ 15
पूर्णिया, पटना, कटिहार........ 16
सुपौल........ 17
पीरपैंती, भागलपुर और रोसड़ा........ 18
सरायरंजन, परबत्ता, सूर्यगढ़ा और शेखपुरा........ 18
बिहार विधानसभा चुनाव पर एक रिपोर्ट........ 19
भाजपा ने जारी किया 'विजन दस्तावेज'........ 21

लेख

कालेधन के विरुद्ध राजग सरकार का अभियान
– **अरुण जेटली**........ 22

अन्य

प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा........ 24
भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 60 साल बाद आयरलैंड की यात्रा........ 27
भारत–जर्मन वार्ता........ 28

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को **दशहरा** की हार्दिक शुभकामनाएं!

सोशल मीडिया से...

फेसबुक

श्री नरेंद्र मोदी

कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का मिलना महागठबंधन नहीं, महास्वार्थबंधन है। ये बिहार के विकास के लिए नहीं, कुर्सी के लिए एक साथ आए हैं। बिहार में जंगलराज कभी नहीं लौटना चाहिए। जंगलराज ने 3 पीढ़ियां बर्बाद की। बिहार को बचाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है।

.....

श्री अमित शाह

नीतीश कुमार के एक कंधे पर जंगलराज के प्रतीक लालू प्रसाद और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली कांग्रेस, तो बिहार का विकास कैसे? नीतीश कुमार खुद को बिहार समझने की भूल कर बैठे हैं और इस बार बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों, पिछड़ों और दलितों के जीवन-स्तर में सुधार लाना है।

.....

श्री राजनाथ सिंह

केन्द्र ने समाज के गरीब और गरीब तबकों के लिए जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है। राजग सरकार जन हितकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को शक्तिशाली बनाने में मदद करती है जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियां उन्हें सरकार पर निर्भर बनाती है।

.....

श्री राजीव प्रताप रूडी

भारत को अगले पांच वर्षों में तीन करोड़ अतिरिक्त कुशल लोगों की आवश्यकता होगी, जिनमें पर्यटन और सरकार में लगभग 50 लाख लोगों की आवश्यकता रहेगी जिसके लिए सरकार ने इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 36 सेक्टर कौंसिलों की स्थापना की है। इन सभी चीजों के बदलने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं।

twitter

श्री नरेंद्र मोदी *@narendramodi*

60 साल महास्वार्थबंधन को दिये, 60 महीने एनडीए को दीजिए, दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनाइये।

.....

श्री अमित शाह *@AmitShahOffice*

जिस नितीश कुमार के एक कंधे पर लालू का जंगलराज और दूसरे पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार है वो बिहार का विकास नहीं कर सकता।

.....

श्री अरुण जेटली *@arunjaitley*

मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। भारत नई परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक एफडीआई वाला गंतव्य बन गया है।

.....

श्री नितिन गडकरी *@nitin_gadkari*

यह हरित राजपथ नीति आगामी वर्षों में लगभग 5 लाख नौकरियां प्रदान करेगी।

.....

श्री जेपी नड्डा *@JPNadda*

हम सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर जोरदार ढंग से काम करते रहेंगे, ताकि सभी को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।

.....

श्री सुशील मोदी @SushilModi

बिहार को चाहिए काम करने वाली सरकार, बदलिए, सरकार बदलिए बिहार।

पाथेय

जो भी कार्य आप लेते हैं उसे गंभीरता से और अच्छी तरह से करें। कभी भी उसे आधा-अधूरा या अपूर्ण नहीं छोड़ें। कभी भी आप संतुष्ट ना महसूस करें, जब तक आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास ना कर लिया हो। अनुशासन एवं सहिष्णुता की आदत विकसित करें। अपनी आस्था, जिससे आप प्यार करते हैं, उसे ना छोड़ें परंतु अपने विरोधियों के दृष्टिकोण को भी समझना सीखें।

- डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

(कलकत्ता विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के अवसर पर 2 मार्च 1935 को दिए गए भाषण का अंश)

सम्पादकीय

भाजपा का कमल खिलेगा महागठबंधन की नैय्या डूबेगी

बिहार में राजनीति गर्म है। राज्य विधानसभा का यह चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। बिहार में राजनैतिक अस्थिरता को स्थिरता प्रदान करने का दायित्व राज्य की जनता के ऊपर आया है। बिहार में जनता ने सभी को आजमाया। पन्द्रह वर्ष लालू राज और जनता ने भाजपा समर्थित जद(यू) का राज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में देखा। भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़कर नीतीश कुमार को नेता बनाया गया, पर यहां नीतीश जी को यह गलतफहमी रही कि वो जो कुछ हैं अपने दम पर हैं, जो सच नहीं था। भाजपा बिहार की जनता को जंगलराज से मुक्ति दिलाना चाहती थी। बिहार में स्थिति यह बन गयी है कि अब चोर-चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। जिस जंगलराज के खिलाफ भाजपा और नीतीश जी ने मुहिम छेड़ी थी, आज वही नीतीश जी भाजपा के साथ विश्वासघात और लालूजी के साथ सांठ-गांठ बना लिया। कुर्सी ने नीतीश जी को इतना नीचे गिरा दिया जिसकी कल्पना आम जनता ने नहीं की थी। अपनी कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने न केवल लालूजी बल्कि उस कांग्रेस का समर्थन ले लिया, जिसका उन्होंने समाजवादी नेता के नाते बचपन से ही विरोध किया। बिहार की जनता साफ तौर पर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज है। जनता का कहना है कि नीतीश जी ने भाजपा को जहां धोखा दिया, वहीं बिहार की जनता को भी उन्होंने लालूजी का साथ लेकर धोखा दिया है। जनता ने 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का साथ इसलिए दिया था कि वे भाजपा के साथ थे और लालूजी और कांग्रेस के विरोध में थे। जनता को जदयू नेता ने मूर्ख समझ लिया। जदयू सत्ता के लिए कहां तक गिर गई है!

बिहार में एक बात आम चर्चा में है कि अबकी बार भाजपा को आजमाना चाहिए। जनता जानती है कि भाजपा नेतृत्व में राज्य में कभी सरकार नहीं बनी। आम आदमी एनडीए को मौका देना चाहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार ने जातिवादी बंधन को तोड़कर श्री नरेन्द्र मोदी का साथ दिया था। यही कारण है कि एनडीए को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें मिलीं। नीतीश कुमार जी का अहम बिहार की जनता ने बुरी तरह से तोड़ दिया। बावजूद इसके उनका अहम चूर नहीं हुआ। उन्होंने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की और जनता को अपना समर्पण दिखाने की कोशिश की। लेकिन कुर्सी के मोह में डूबे नीतीश कुमार ने फेंकने वाले गिलास की तरह जीतन राम मांझी को हटा दिया। नीतीश कुमार के दलित प्रेम का भांडा स्वयं फूट गया। वहीं लालू जी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को समर्थन देकर अपना दलित विरोधी रवैया जनता के सामने ला दिया।

आज बिहार में लालू जी और नीतीश जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्वे में मात खा रहे महागठबंधन के नेता अपना आपा खो चुके हैं। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जदयू और राजद के नेता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शर्मनाक ही नहीं बल्कि इस बात का संकेत दे रहा है कि महागठबंधन लड़ाई से पहले अपनी हार मान चुका है। बिहार की जनता का पूरा विश्वास भाजपा और देश के प्रधानमंत्री के साथ है। बिहार की धरती से एक ही आवाज आ रही है, सबका साथ, सबका विश्वास। बिहार जातिगत आदि सभी कारणों से ऊपर है। बिहार के नौजवानों ने साफ-साफ संकेत दे दिए हैं कि अबकी बार, भाजपा सरकार। बिहार की जनता ने पूर्व में भी अपने विवेक से देश को दिशा दी है। पांच चरणों में संपन्न होने वाला बिहार राज्य का विधानसभा चुनाव पूरी तौर से महागठबंधन के चरण उखाड़ फेंकेगा। एक ओर जहां भाजपा का कमल बिहार में खिलेगा, वहीं जदयू-राजद और कांग्रेस रूपी महागठबंधन की नैय्या डूबेगी।■

संगठनात्मक गतिविधियां : एनडीए रैली – बांका

हमारी सभी समस्याओं का समाधान विकास में निहित है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर को बिहार के बांका में आयोजित परिवर्तन रैली में उमड़े विराट जन समूह को सम्बोधित किया और बिहार के विकास के लिए भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की राजग सरकार बनाने की अपील की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार बिहार की जनता दो दिवाली मनायेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने बिहार में भाजपा के नेतृत्व में राजग के रूप में विकास और सुशासन के लिए स्थिर और मजबूत सरकार लाने का मन बना लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाए बिना हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि बिहार का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है और साथ ही साथ सबसे पहली जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन हो, किसानों के कल्याण के लिए प्रगतिशील नीतियां और नारी शक्ति के विकास का सपना संजोये मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार ने सामंतवाद, पूंजीवाद, अहंकारवाद, अलगाववाद, फासीवाद और वंशवाद को वर्षों तक झेला है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक बार आप विकासवाद को वोट दें क्योंकि हमारी सभी समस्याओं का समाधान विकास में निहित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.65 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए जो भी कर रही है, वह बिहार की जनता का हक है जिससे आज तक बिहार की जनता को महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मुझे इसका सम्मान दिया है और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हालिया अमेरिकी दौरे में अमेरिका में रहने वाले बिहार के लोगों से बात की और उन सबकी इच्छा बिहार को आगे बढ़ता हुआ देखने की थी। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर बिहार को विकास के पथ पर ले जाना है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बिहार को दिए गए विशेष पैकेज पर सवालिया निशान लगाने के लिए बिहार के महागठबंधन और बिहार की वर्तमान सरकार को आड़े-हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों पर इस बात का भरोसा कतई नहीं किया जा सकता कि वह गरीब की भलाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को जनता तक पहुंचा पाएगी भी या नहीं। उन्होंने कहा कि आज बिहार में जो सरकार है, उनमें इतना अहंकार है कि वह मेरी तरफ से भेजे गए वित्तीय मदद को भी कहीं वापस न कर दे।

उन्होंने कहा कि इनको तो धोखा देने की आदत है, इन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया, श्री जीतन राम मांझी को धोखा दिया, यहां तक कि इन्होने जनादेश का भी अपमान किया है, बिहार की जनता सब समझती है और वह अब इन लोगों के बहकावे में आनेवाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट में अगर हम बिहार की तुलना झारखंड से भी करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि झारखंड में विकास के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है जबकि बिहार और अधिक पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में उद्योग और व्यापार की आसान

'जंगलराज और विकास के बीच है लड़ाई'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव को जंगलराज और विकास के बीच लड़ाई करार देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि राज्य के लोग विकासराज के लिए वोट करेंगे न कि जंगलराज के लिए। श्री मोदी ने यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस विधानसभा चुनाव में एक तरफ जंगलराज तो दूसरी तरफ विकासराज है। यह लड़ाई इन दोनों के बीच है और अब जनता को फैसला करना है कि उसे जंगल राज चाहिए या विकास राज।

श्री मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि जो लोग जयप्रकाश नारायण के गीत गाते थे, वही आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। क्या यह जेपी के साथ धोखा नहीं है। ये महागठबंधन नहीं, महास्वार्थबंधन है।

श्री मोदी ने कहा कि लालू जी ने यदुवंश को अपमानित किया, जबकि यदुवंश ने इनको सत्ता पर पहुंचाया। आज यदुवंश के लोगों को वे कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे मन में सवाल उठता है कि शैतान को यही पता कहां से मिला। दुनिया में शैतान को कोई ठिकाना नहीं मिला, यही एक ठिकाना मिला। उन्होंने रिश्तेदार की तरह शैतान को पहचान भी लिया। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारी लड़ाई इंसानों से है, तो अब पता चला कि हमारे पीछे शैतान पड़ा है।

उन्होंने कहा कि जंगलराज का सबसे बड़ा उद्योग अपहरण था। आए दिन डाक्टरों, इंजीनियरों और व्यवसायियों का अपहरण होता था, अब वही यादें फिर से ताजा हो रही है। बिहार सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच अपहरण की चार हजार घटनाएं हुई है। अब लोगों को तय करना है कि क्या फिर से बिहार में अपहरण के दिन आने देने है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल शासनकाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि जंगलराज के समय जब राज्य में लोग कोई नई गाड़ी खरीदते थे तो उन्हें चिंता होती थी कि कोई नेता गाड़ी उठाकर चला जाएगा। जान का भी डर लगा रहता था। उन्होंने कहा कि डर के कारण माताएं शाम के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। बिहार के लोगों ने यह दिन देखा है और लोग उसे भूले नहीं है इसलिए उन्हें विश्वास है कि राज्य के लोग विकासराज के लिए वोट करेंगे न कि जंगलराज के लिए। ■

राह के मामले में बिहार, झारखण्ड से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि बिहार में काला ज्वर की स्थिति अभी भी काफी गंभीर है जबकि झारखंड ने इस पर काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि झारखंड ने भाजपा को चुना और अब झारखंड विकास के पथ पर नित नए आयाम हासिल करता जा रहा है, हम बिहार को भी विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और इसलिए विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम बिहार की जनता से वोट की अपील करने आये हैं।

प्रधानमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार का भाग्य बदलने के लिए इस चुनाव में आप भारी मात्रा में वोट कीजिए और ऐसी सरकार चुनिए जो नौजवानों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किये जा सकें, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, किसानों की हितों की रक्षा हो और बिहार विकास के पथ पर आगे बढे।

प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद और माओवाद से जुड़े लोगों से अपील करते हुए कहा कि बुलेट से विनाश और बैलेट से विकास होता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से समस्या का समाधान नहीं होता, धरती को लाल करने से भाग्य नहीं बदलता।

समय की मांग है कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में आएं तथा कंधे से कंधे से मिला कर अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि आज गांधी जयंती के दिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ें।

संगठनात्मक गतिविधियां : जनसभा, कोल्लम (केरल)

केरल को कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुक्त राज्य बनाना है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 सितंबर को कोल्लम में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित किया और जनता से केरल में भाजपा को मौका देने की अपील की। उन्होंने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि केरल में जनता और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और हमें आने वाले विधान सभा चुनाव में केरल को कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुक्त राज्य बनाना है।

उन्होंने कहा कि भले ही 2014 के लोक सभा चुनावों में भाजपा को केरल में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन केरल की 21 प्रतिशत जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में अपना मतदान देकर बता दिया कि केरल की जनता कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बहकावे में अब और आनेवाली नहीं है।

श्री शाह ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए सतत तत्पर हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा-नीत केंद्र सरकार ने पिछले 15 महीनों से गरीबों, शोषितों और वंचितों के उत्थान तथा सामाजिक कल्याण के लिए अनवरत कार्य किये हैं और अनेक परिवर्तनात्मक योजनाओं की नींव रखी है जिसके आशातीत परिणाम धरातल पर दिखने शुरू हो गए हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा हो या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना। श्री शाह ने कहा कि विकास के जरिये गरीबों की सेवा और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए 'मेक इन इंडिया' अभियान ने जबरदस्त सफलता हासिल की है और दुनिया भर की कंपनियों में भारत में निवेश को लेकर होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के जरिये युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देने जाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है और अब देश के युवाओं के पास रोजगार के अनेकों अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के और उनके सहयोगियों की सरकार की नाकामी का जीता जागता उदहारण है कि आजादी के 68 वर्ष बाद भी देश के 60 करोड़ लोगों का एक अदद बैंक खाता तक नहीं था जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाये गए प्रधानमंत्री जन-धन खाता योजना के तहत 15 करोड़ परिवारों के पास अब अपना बैंक खाता है और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए जनता को दी जाने वाली मदद अब सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचती है।

श्री शाह ने आगे बोलते हुए कहा कि आज भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया में मान-सम्मान बढ़ा है और यह मान-सम्मान देश की 125 करोड़ जनता का सम्मान है।

श्री शाह ने केरल की जनता से अपील करते हुए कहा कि केरल में आपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट - दोनों को बार-बार मौका दिया लेकिन केरल में प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर मात्रा में रहते हुए, राज्य में पर्यटन की अपार संभावना और मेधावी मानव संसाधन के बावजूद आज केरल विकास में पीछे क्यों है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो देश से लगभग समाप्त हो चुकी है और कम्युनिस्ट विश्व से समाप्त हो चुकी है, इसलिए इस बार केरल की जनता भाजपा पर भरोसा करे और भाजपा को केरल में शासन का अधिकार दे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ - सबका विकास' की अवधारणा के साथ भाजपा केरल को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाएगी। ■

सरकार की उपलब्धियां

मुद्रा योजना का उद्देश्य कमजोर उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है

मुद्रा योजना का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों से आने वाले उन उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है, जो आमतौर पर ऋण के लिए सूदखोर महाजनों पर निर्भर रहते हैं। इस योजना के 120 भागीदार हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई शामिल है।

इस साल के आरम्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के अनिधिक अनुभाग की सहायता के उद्देश्य से मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड) की शुरुआत की थी। असंगठित क्षेत्र में तकरीबन 5.7 करोड़ उद्यमी हैं जो लगभग 11 करोड़ नौकरियां सृजित करते हैं। भारत में अनुमानित 24 करोड़ परिवार हैं। इस प्रकार आर्थिक संरचना के निचले स्तर पर समाज के ये वर्ग अनिधिक थे। वे ब्याज के शोषक दर (24 से 36 प्रतिशत) पर ऋण के लिए महाजनों पर निर्भर थे। भारत का औद्योगिक, सेवा और कृषि क्षेत्र अभी भी इतना मजबूत नहीं हैं कि इन्हें रोजगार में समावेशित किया जा सके।

मुद्रा योजना का अब शुभारम्भ कर दिया गया है। इसके 120 भागीदार हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई भी शामिल है। 2015-16 के चालू वित्त वर्ष में भारतीय समाज के इन अनिधिक वर्गों को 1.22 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि दी जाएगी। ऋण की तीन श्रेणियां हैं- शिशु- 50,000 रुपये तक, किशोर- 5,00,000 रुपये और तरुण-10,00 000 रुपये। यह योजना

24,000 करोड़ रुपये ऋण की राशि पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इस समय तक 37 लाख लाभार्थी हैं और उम्मीद है कि लाभार्थियों की संख्या इस वर्ष 1. 5 करोड़ को पार कर जाएगी। साल दर साल यह संख्या बढ़ती चली जाएगी। अतीत के अनुभव यह संकेत देते हैं कि ऐसे सूक्ष्म वित्त और इसी तरह के ऋण की वसूली दर निहायत ही ज्यादा है और बहुत कम डिफाल्टर हैं। भारतवर्ष सभी को रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर को सक्षम करने के लिए, उन्हें स्वरोजगार और आत्म-निर्भर होने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काफी सशक्त साबित होगी।

अगले कुछ वर्षों के लिए जारी रहेगी। इस योजना के लक्षित लाभार्थी वे छह करोड़ लोग हैं, जिन्हें भारत के छोटे उद्यमियों के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। इन सभी को डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा और इन्हें एटीएम के माध्यम से पैसे के निकासी की अनुमति होगी। ये लोग प्रतिभूति नहीं जुटा सकते हैं, और इसलिए, उन पर ऋण के लिए प्रतिभूतियां प्रस्तुत की आवश्यकता लागू नहीं होगी। इन ऋणों को व्यक्तिगत ताकत और राजनीतिक संपर्क के बल पर नहीं अपितु इन संभावित उद्यमियों के व्यापार प्रस्तावों के आधार पर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुद्रा योजना के समर्थन में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने ग्रामीण दिल्ली में 25 सितंबर 2015 को एक अभियान का शुभारंभ किया था। यह पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित किया गया था। इसके लाभार्थी सब्जी विक्रेता, छोटी दुकान वाले, ब्यूटी पार्लर और बुटीक से जुड़ी महिलायें, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर इत्यादि थी।

24,000 करोड़ रुपये ऋण की राशि पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इस समय तक 37 लाख लाभार्थी हैं और उम्मीद है कि लाभार्थियों की संख्या इस वर्ष 1.5 करोड़ को पार कर जाएगी। साल दर साल यह संख्या बढ़ती चली जाएगी। अतीत के अनुभव यह संकेत देते हैं कि ऐसे सूक्ष्म वित्त और इसी तरह के ऋण की वसूली दर निहायत ही ज्यादा है और बहुत कम डिफाल्टर हैं। भारतवर्ष सभी को रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर को सक्षम करने के लिए, उन्हें स्वरोजगार और आत्म-निर्भर होने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काफी सशक्त साबित होगी। ■

लागू हुआ काला धन कानूनः
638 ने की 4147 करोड़ रुपये कालाधन की घोषणा

विदेशों में जमा बेहिसाब धन सम्पत्ति के खिलाफ नये कानून सरकार द्वारा दी गयी अनुपालन सुविधा के तहत 90 दिन की अवधि में लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपए के धन का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपए बतायी गयी थी। राजस्व सचिव ने 5 सितंबर को कहा कि पिछले सप्ताह समाप्त इस अवधि में कुल 638 जानकारियां मिली जिनके तहत विदेश में 4,147 करोड़ रुपए की गैरकानूनी संपत्ति की घोषणाएं की गई हैं। अनुपालन की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हुई। सरकार को इन पर कर और जुर्माने के रुपए में कुल 2,488.20 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

सरकार ने एक अक्टूबर को घोषणा की थी की अनुपालन सुविधा के तहत कुल 3,770 करोड़ रुपए की अघोषित राशि की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह जानकारी प्राथमिक गणना पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि लिफाफों के जरिये मिली सूचनाओं को मिला कर कुल आंकड़ा 4,147 करोड़ रुपए बैठता है। साथ ही कहा कि पहले दी गयी जानकारी में लिफाफों की गिनती तो हुई थी पर उनकी घोषित राशि एक अक्टूबर के आंकड़ों में नहीं दिखाई जा सकी थी।

अनुपालन सुविधा के तहत 30 सितंबर को समाप्त 90 दिन की अवधि में लोगों को विदेशों में जमा अपनी धन सम्पत्ति का ब्योरा आन लाइन देने की भी सुविधा दी गयी थी। इस अवधि के अंदर विदेश में काला धन रखने की घोषणा करने वाले को 31 दिसंबर से पहले संपत्ति पर 30 फीसदी कर और अतिरिक्त 30 फीसदी जुर्माना देना होगा। काले धन की घोषणा करने की रियायत अवधि एक जुलाई से शुरू हुई थी। इस दौरान संपत्ति की घोषणा नहीं करने वाले पर अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (कराधान) कानून-2015 (काला धन कानून) के तहत संपत्ति का 30 फीसदी कर और अतिरिक्त 90 फीसदी जुर्माना यानी, प्रभावी तौर पर कुल 120 फीसदी कर लगाया जाएगा।

दरअसल, अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फाटका) के तहत अमेरिका से सूचनाएं मिलनी शुरू हो गयी हैं। भारत ने अमेरिका के साथ इस काननू के तहत कर सूचनाओं के आदान प्रदान का करार किया है। यही नहीं, स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी के खाताओं की सूची से जुड़े 43 मामलों में 132 मुकदमे दर्ज हुए हैं।

विदेशों में जमा बेहिसाब धन सम्पत्ति के खिलाफ नये कानून सरकार द्वारा दी गयी अनुपालन सुविधा के तहत 90 दिन की अवधि में लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपए के धन का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपए बतायी गयी थी। राजस्व सचिव ने 5 सितंबर को कहा कि पिछले सप्ताह समाप्त इस अवधि में कुल 638 जानकारियां मिली जिनके तहत विदेश में 4,147 करोड़ रुपए की गैरकानूनी संपत्ति की घोषणाएं की गई हैं।

काले धन की घोषणा के बाद राजस्व अधिकारियों ने कहा कि जो भी मिला, हमने स्वीकार कर लिया। अब हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने काले धन की घोषणा नहीं की दरअसल, घोषणा स्वीकार करने के लिए निर्दिष्ट अधिकारी 30 सितंबर 2015 को मध्य रात तक काम करते रहे, क्योंकि आयकर कार्यालय में काले धन की घोषणा करने वालों का तांता लग गया था और ई-फाइलिंग पोर्टल मध्य रात तक खुला रहा। दरअसल, काले धन की घोषणा को सरल करने के लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाए और इस संदर्भ में लोगों की कई जिज्ञासाओं का उचित समाधान किया गया।

वास्तव में काला धन अधिनियम में पहली बार विदेश में जमा रखी गई संपत्ति पर देश में कर लगाने का प्रावधान किया गया है। सरकार के पास विदेश में जमा काले धन के बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, यह रकम 466 अरब डॉलर से लेकर 1,400 अरब डॉलर तक हो सकती है।

काला धन कानून एक अक्टूबर से लागू

अनुपालन खिड़की बंद होने के साथ ही काला धन कानून 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि अनुपालन खिड़की बंद होते ही कानून अपने सभी प्रावधानों के साथ काला धन की घोषणा नहीं करने वालों पर लागू हो जाएगा।■

सरकार की उपलब्धियां

विदेशी निवेश में भारत है नंबर वन

भाजपानीत राजग सरकार उचित नीतियों व त्वरित प्रयासों के चलते आज भारत विदेशी निवेश के मामले में नबंर एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना 'मेक इन इंडिया' के तहत देश में निवेश तेजी से बढ़ा है। विदेशी निवेश के मामले में भारत ने चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स (लंदन) की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली छमाही के दौरान चीन को 28 अरब डॉलर, अमेरिका को 27 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है वहीं भारत को इन दोनों देशों से ज्यादा 31 अरब डॉलर का निवेश मिला है।

भारत ने 2015 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के मामले में चीन और अमेरिका को पछाड़ दिया। आलोच्य अवधि में भारत को 31 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हासिल हुआ है। 29 सितंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में भारत पूंजी निवेश के मामले में पांचवे नंबर पर था। इससे ऊपर चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको हुआ करते थे। फाइनेंशियल टाइम्स (लंदन) में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से 2015 की पहली छमाही में भारत, चीन और अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आकर्षक देश बन गया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, 2015 की पहली छमाही में भारत को 31 अरब डॉलर एफडीआई मिला। वहीं, चीन को 28 अरब डॉलर और अमेरिका को 27 अरब डॉलर एफडीआई मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक, एक ही साल में जब एफडीआई आकर्षित करने वाले देशों में इस बाबत कमी देखी गई, भारत में यह अधिक रही।

एफटी के मुताबिक 2014 में विदेशी निवेश के लिहाज से प्रमुख देशों में जब इसकी मात्रा घट रही थी तब भारत में यह 47 फीसदी बढ़ी और 24 अरब डॉलर हो गई। एफटी का कहना है कि भारत पिछले साल की तुलना में काफी आगे बढ़ा और यहां साल के मध्य में निवेश का स्तर दोगुना हुआ है। पिछले साल की पहली तिमाही के 12 अरब डॉलर के निवेश की तुलना में जून 2015 में एफडीआई 30 अरब डॉलर रहा।

भारत ने 2015 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के मामले में चीन और अमेरिका को पछाड़ दिया। आलोच्य अवधि में भारत को 31 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हासिल हुआ है।

पिछले कई सालों से एफडीआई के मामले में अमरीका और चीन के बीच बराबर की टक्कर रही है। पिछले साल जहां अमरीका कुल प्रोजेक्ट्स को लेकर पहले स्थान पर रहा, वहीं चीन कुल खर्च को लेकर प्रथम स्थान पर रहा। साथ ही भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 16 पायदान की छलांग लगाई है और अब वो 55वें नंबर पर पहुँच गया है। कुल सूची 140 देशों की है। यह सूचकांक संस्थानों, व्यापक आर्थिक माहौल, शिक्षा, बाजार का आकार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है।

गौरतलब है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ठीक उसी दिन आई जब भारत की विदेशी निवेश प्रस्तावों पर नजर रखने वाली संस्था विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। यही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल में ही अमरीका में सिलिकॉन वैली के दौरे पर थे और इसे भी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने का सरकार का प्रयास रंग लाने लाने लगा है क्योंकि भारत नई परियोजनाओं के लिये सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला गंतव्य बन गया है। श्री जेटली ने ट्वीट करके कहा कि यह संतुष्ट करने वाला है, हमारा प्रयास रंग लाने लगा है। भारत नई परियोजनाओं के लिये सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला गंतव्य बन गया है। ■

जीवन का ध्येय

– पं. दीनदयाल उपाध्याय

दीनदयालजी विचारक राजनेता थे। प्रस्तुत लेख उन्होंने 'पांचजन्य' में भाद्रपद कृष्ण 9, वि.स.2006 को लिखा था। इसमें उन्होंने बताया है कि जब तक भारत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता तब तक विश्व की प्रगति में सहायक नहीं हो सकता। न तो वह जीवन के सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा और न ही मानव की स्वतंत्रता का। हम यहां इस लेख का प्रथम भाग प्रकाशित कर रहे हैं:

विश्व का प्रत्येक प्राणी सतत् इस बात का प्रयत्न करता रहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, वह जीवित रहे। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह दूसरे अनेक प्राणियों को अस्तित्वहीन करने का प्रयत्न करता रहता है तथा स्वयं उसको अस्तित्वहीन करनेवाली शक्तियों से निरंतर अपनी रक्षा करता रहता है। विनाश और रक्षा के इन प्रयत्नों की समष्टि का ही नाम जीवन है। इन प्रयत्नों की भिन्नता ही भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवनों का कारण है तथा इनकी सफलता या असफलता ही विभिन्न प्राणियों के विकास या विकार का मापदंड है। मानव भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आदि मानव की सृष्टि और तब से अब तक का इतिहास इन प्रयत्नों का ही इतिहास है। किंतु मनुष्य विश्व के प्राणियों से अधिक विकसित है उसका अस्तित्व केवल प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही निभर नहीं करता किंतु उसके जीवन में भौतिकता के साथ-साथ आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का भी समावेश होता है। मनुष्य के जीवन का ध्येय श्वासोच्छ्वास तथा श्वासोच्छ्वास की क्रिया को बनाए रखना ही नहीं है, किंतु इससे भिन्न है। वह तो श्वासोच्छ्वास मात्र जीवन को साधन मानता है, साध्य नहीं। उसका साध्य तो उपनिषदों के शब्दों में है-

'आत्मा वा रे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निर्दिध्यासितव्यः।'

वह आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, उसे समझना चाहता है, अपनी संपूर्ण क्रियाओं को उस अनुभूति के प्रति लगाता है।

हमारी प्रेरक शक्ति

यह आत्मा क्या है जिसके लिए मानव इतना तड़पता है? इस संबंध में अनेक मतभेद हैं और इन्हीं मतभेदों के कारण विश्व में अनेक संप्रदायों की सृष्टि हुई है। अनेक मनीषियों ने इस आत्मा को विश्व का आदि कारण, उसका कर्ता, धर्ता एवं हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को ही माना है। उनका कथन है कि वही एकमेव शक्ति है। जो संपूर्ण विश्व को चला रही है तथा प्रत्येक प्राणी उस ओर ही बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वह उसी में मिल जाना चाहता है और इसलिए मानव का प्रयत्न उस परब्रह्म का साक्षात्कार ही है। उस परब्रह्म में ही पूर्णता होने के कारण 'सत्यं शिवं और सुन्दरं' की पूर्णाभिव्यक्ति होने के कारण ही मनुष्य इन गुणों की ओर आकर्षित होता है तथा जीवन के हर क्षेत्र में इन गुणों की आंशिक अनुभूति करता हुआ पूर्ण साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहता है। कुछ विद्वान् इस अदृश्य शक्ति में विश्वास न करते हुए केवल हृदय जगत् में ही विश्वास रखते हैं तथा उसमें भी मानव के विकास को (उसके सुख-साधन-संपन्न जीवन को) ही परम लक्ष्य मानकर सुख की प्राप्ति के प्रयत्नों को ही मानव जीवन का एकमेव कर्तव्य समझते हैं। उनके विचारों में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है अपितु यदि गहराई से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि मानव को एकता की अनुभूति तथा उसको सुखमय बनाने की इच्छा को प्रेरक शक्ति निश्चित ही दृश्य सृष्टि से भिन्न कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो इस दृश्य जगत् को परिव्याप्त किए हुए प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में संपूर्णता को, एकात्मता की भावना उत्पन्न करता है। उस शक्ति को आप चाहे जो नाम दें किंतु यह निश्चित है कि उसकी ओर प्रत्येक मानव अग्रसर है तथा मानवता के कल्याण की भावना किसी स्वार्थ का परिणाम नहीं किंतु आत्मानुभूति की इच्छा का परिणाम है। अज्ञानवश मानव आत्मा के स्वरूप को संकुचित करने का प्रयत्न करता है किंतु सत्य का ज्ञान सतत् अज्ञान पटल को भेदने के लिए प्रयत्नशील होता है।

अपनी प्रतिमा का विकास

संपूर्ण सृष्टि को एकात्मता के साक्षात्कार का ध्येय सम्मुख रखते हुए भी मानव अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसकी ओर अग्रसर होता है। उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न भागों में रहनेवाला मानव भी संपूर्ण मानव को आंतरिक एकता

की भावना रखते हुए तथा उसकी पूर्णानुभूति की इच्छा रखते हुए भी प्रकृति की साधनों एवं उनको अपने नियंत्रण में करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में अपनी एक विशिष्ट दिशा निश्चित कर लेता है, उसकी कुछ विशेषताएँ हो जाती हैं, उसको अपनी निजी प्रतिभा का विकास हो जाता है। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी एक है किंतु उसके ऊपर स्थित पहाड़, पर्वत, सागर और वन उसके भिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति अपना प्रभाव उस प्रदेश के मानव पर डाले बिना नहीं रहते तथा उस विशिष्ट भू-भाग के मनुष्य पूर्णानुभूति के प्रयत्नों में अपना विकास निश्चित दिशा में करते हैं। उनका अपना एक निजी स्वत्व हो जाता है जो कि उसी प्रकार की दूसरी इकाइयों से उसी प्रकार भिन्न होता है जैसे कि एक ही सेना के विभिन्न अंग। आधुनिक युद्ध में जल, थल और वायु सेना जिस प्रकार अपनी-अपनी पद्धति से एक ही युद्ध को जीतने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्र एक ही मानवता की अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जल, थल और वायु सेना में कार्य करने में सैनिकों को अपनी विशेष प्रतिभा का विकास होता है तथा वे अपनी निजी पद्धति से शत्रु को पराजित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तीनों सेनाओं में सामंजस्य रहना तो अच्छा है किंतु यदि किसी सेना के सैनिक अपनी पद्धति को ही सत्य मानकर दूसरी सेना के सैनिकों पर प्रभाव जमाने का प्रयत्न करें अथवा उसकी प्रतिभा को नष्ट करना चाहें तो उनका यह प्रयत्न अंतिम ध्येय की पूर्ति में बाधक होगा तथा आक्रमित सेना के सैनिकों का कर्तव्य होगा कि वे आक्रमणकारी सैनिकों से ही प्रथम युद्ध करके उनकी बुद्धि को ठिकाने पर ला दें। इसी प्रकार यदि किसी सेना के विशेष प्रभाव को देखकर अथवा किसी विशेष क्षेत्र में उनकी विजयों को देखकर अथवा आक्रमणकारी सेना की सामर्थ्य का अनुभव करते हुए कोई सेना अपनी पद्धति, अपने प्रयत्न तथा अपनी प्रतिभा को तिलांजलि देकर उस दूसरी सेना की विशेषताओं को और उसमें भी विशेषकर उसके बाह्य स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करती है तो वह तो स्वतरू नष्ट हो ही जाएगी अपितु मानव की अंतिम विजय में भी अपना दायित्व नहीं निभा पाएगी।

संपूर्ण सृष्टि को एकात्मता के साक्षात्कार का ध्येय सम्मुख रखते हुए भी मानव अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसकी ओर अग्रसर होता है। उसी प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न भागों में रहनेवाला मानव भी संपूर्ण मानव को आंतरिक एकता की भावना रखते हुए तथा उसकी पूर्णानुभूति की इच्छा रखते हुए भी प्रकृति की साधनों एवं उनको अपने नियंत्रण में करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में अपनी एक विशिष्ट दिशा निश्चित कर लेता है, उसकी कुछ विशेषताएँ हो जाती हैं, उसको अपनी निजी प्रतिभा का विकास हो जाता है।

आक्रमण वृत्ति

विश्व के अनेक राष्ट्रों का इतिहास उपर्युक्त उदाहरण की भावनाएँ ही परिलक्षित करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट पद्धति को सत्य समझने लगता है तथा अपने को ही एकमेव प्रतिभावान मानकर दूसरे राष्ट्रों पर अपनी पद्धतियों को लादने का प्रयत्न करता है। यदि यह प्रयत्न शांतिमय होता तो भी कुछ बात नहीं किंतु वह जबरदस्ती अपने सत्य को दूसरों के गले उतारना चाहता है। मानव के सुख और वैभव को भी वह अपने राष्ट्र के सुख और वैभव तक ही सीमित करके दूसरे राष्ट्रों के सुख और शांति को नष्ट करता है, उसके प्राकृतिक विकास में बाधा डालता है। फलतः एक राष्ट्र दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे गुलाम बना लेता है। परतंत्र राष्ट्र का जीवन प्रवाह रुद्ध हो जाता है। उसके घटक किसी-न-किसी प्रकार श्वासोच्छवास तो करते रहते हैं किंतु वे अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। भौतिक दृष्टि से सुखोपभोग करनेवाले व्यक्ति भी परतंत्रता का ताप अनुभव करते रहते हैं क्योंकि उनका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, उनकी भावनाओं पर ठेस पहुँचती है तथा उनकी प्रतिभा कुंठित होने लगती है, उनकी आत्मानुभूति का मार्ग बंद हो जाता है। युगयुगों से उनकी प्रतिभा ने प्रस्फुटित होकर जिन विशेष वस्तुओं का निर्माण किया होता है, उसकी अवमानना होने लगती है तथा उनके विनाश का पथ प्रशस्त हो जाता है। उस राष्ट्र की भाषा, संस्कृति, साहित्य और परंपरा नष्ट होने लगती है, उसके महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा निर्माण की जाती है तथा उसके नैतिक मापदंडों को निम्नतर ठहराया जाता है। उसके जीवन की पद्धतियाँ विदेशी पद्धतियों से आक्रांत हो जाती हैं तथा विदेशी आदर्श उसके अपने आदर्शों का स्थान ले लेते हैं। फलतः उस राष्ट्र के व्यक्तियों की दशा विक्षिप्त व्यक्ति के समान हो जाती है, अपनी प्रकृति, स्वभाव और प्रतिभा के अनुसार कार्य करने की सुविधा न रहने के कारण वे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने से ही वंचित नहीं रह जाते अपितु पतन की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं।

...क्रमशः

श्रद्धांजलि

प्रो. राम कापसे नहीं रहे

प्रो. राम कापसे का निधन 29 सितम्बर 2015 को मुम्बई (महाराष्ट्र) में हो गया। वे रामबाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने लम्बी बीमारी के बाद अपने गांव कल्याण में अंतिम सांस ली। वे 2004-2006 में अंडमान और निकोबार के राज्यपाल रहे। 1 दिसम्बर 1933 को नासिक में उनका जन्म हुआ था। उनके माता-पिता का निधन प्रारंभिक आयु में हो गया था और उनकी बहन ने पालन पोषण किया था। बम्बई विश्वविद्यालय से एक और एलएलबी उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने शिक्षाविद्, लेखक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व डीजी रूपरेल कॉलेज में संस्कृत और मराठी के लेक्चरर के रूप मे काम किया।

वे अत्यंत कृपालु व्यक्ति थे और उन्होंने गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने नशे के आदी लोगों के लिए पोर्टब्लेयर में नशा छुड़ाने के लिए कार्य किया। उनके जीवन काल में सेल्युलर जेल में स्वतंत्र ज्योति का प्रारम्भ हुआ और भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध पर एक नई दीर्घा बनाई। प्रो. राम कापसे के दुखद निधन के बाद पार्टी ने एक महान संगठनकर्ता नेता और आदर्श निर्वाचित प्रतिनिधि खो दिया। वह महाराष्ट्र विधानसभा में 1990 में भाजपा विधानसभा पार्टी के नेता थे और वे संसद के लिए भी चुने गए थे। ■

शोक संदेश

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने पूर्व लोक सभा सांसद प्रोफेसर राम कापसे के निधन पर शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र से पूर्व लोक सभा सांसद प्रोफेसर राम कापसे के निधन के साथ ही हमने एक महान संगठक राजनेता और एक आदर्श निर्वाचित प्रतिनिधि को खो दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रो कापसे मराठी साहित्य के एक लोकप्रिय शिक्षक थे। वह रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।

प्रोफेसर कापसे राजनेताओं की उन पुरानी पीढ़ी में से थे, जिनके लिए राजनीति एक पूर्णकालिक पेशा नहीं था। वह उन लोगों में से एक थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत नींव का निर्माण किया। सांसद के रूप में और उपराज्यपाल के रूप में भी, दोनों रूपों में वह एक आदर्श लोक सेवक बने रहे।

सुनामी के कठिन समय में अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल के रूप में अपने अत्यंत कठिन प्रयासों के माध्यम से सक्रिय रूप से राहत और पुनर्वास कार्यों को संभालते हुए उन्होंने नए मानक स्थापित किए। लंबे वक्त के लिए, वह एक विद्वान राजनेता के रूप में याद किये जायेंगे। दु:ख की इस घड़ी में, भारतीय जनता पार्टी दिवंगत नेता के परिवार के साथ है।■

प्रधानमंत्री ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग पर विचार प्रकट करते हुए लिखा कि निस्वार्थ सेवा की मसाल और उत्कृष्ट आयोजक। मैं अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें शीश झुकाता हूं। आइए दीनदयाल जी के पथ का अनुकरण करें और ऐसा भारत बनाएं जो विकसित और न्यायप्रिय हो। ■

बिहार विधानसभा चुनावों पर विशेष

बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। मुख्य मुकाबला राजग और महागठबंधन के बीच है। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पांच चरणों में चुनाव होने हैं। 8 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं एवं कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित कर राजग प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान कर रहे हैं। हम यहां उनके भाषणों का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं :

बेगूसराय

भाजपा की परम्परा ही विकास की रही है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 30 सितंबर को बिहार के बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और बिहार की जनता का ध्यान चुनाव में विकास के मुद्दे से भटकाकर वे पुन: एक बार जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार के आरक्षण के झूठे प्रचार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जनता उनके सफेद झूठ से भ्रमित होने वाली नहीं है। उन्होंने आरक्षण पर भाजपा के इस संकल्प को फिर से दोहराया कि भाजपा वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की पक्षधर है और इस पर किसी भी तरह के पुनर्विचार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय से ही भाजपा आरक्षण के पक्ष में रही है और इस पर किसी भी तरह के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर बिहार में 24 घंटे बिजली चाहिए, बिहार में निवेश चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोजगार के पर्याप्त अवसर बनने चाहिए, यदि राज्य को अपराध, भ्रष्टाचार और जंगलराज से मुक्ति चाहिए तो बिहार की जनता को एकमत से फैसला करके राज्य में दो-तिहाई की पूर्ण बहुमत से भाजपा-नीत सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव राजनीति की एक नई दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से समाज में उच्चतम आदर्शों की परंपरा का निर्वहन करने वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' और पिछले 15 महीनों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएँ और बिहार में विकास और इसके गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना के लिए राज्य में भाजपा नेतृत्व में दो तिहाई बहुमत की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाएं।

औरंगाबाद

हमारा लक्ष्य बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाना

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को बिहार के औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मलेन को सम्बोधित किया और बिहार से भ्रष्टाचार, जंगलराज और कुशासन की सरकार को जड़ से उखाड़ कर राज्य में भाजपा की अगुआई में राजग की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि बिहार व्यापार, कृषि, कला, शिक्षा और विज्ञान का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अखंड भारत पर शासन करनेवाला बिहार आज बिहार विकास के मापदंडों पर देश के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ गया है।

उन्होंने कहा कि अभी भी बिहार में बिजली गाँवों तक नहीं पहुँची है, अभी तक गाँवों तक पक्की सड़कें नहीं पहुँची

है, शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है, अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए युवा पलायन करने पर बाध्य हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के विकास के मूल में बिहार के युवाओं का पसीना है, बिहार के युवाओं ने देश को बनाया, लेकिन बिहार अभी भी विकास में काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि श्री लालू यादव और श्री नीतीश कुमार फिर से छद्म रूप में कपड़े बदल कर बिहार को जंगलराज के दौर में घसीटने के लिए आ गए हैं लेकिन जनता इस बार के चुनाव में इन्हें कड़ा सबक सिखाएगी।

पूर्णिया

लालू यादव जंगलराज एवं कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्रतीक

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को बिहार के पूर्णिया की चुनावी सभा में एक विशाल जन-समुदाय को सम्बोधित किया और सीमांचल की जनता से बिहार से भ्रष्टाचार, जंगलराज और कुशासन की सरकार को जड़ से उखाड़ कर राज्य में भाजपा की अगुआई में दो-तिहाई बहुमत की राजग सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'यह स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार राजग बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई में दो तिहाई की बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।'

उन्होंने कहा कि एक तरफ श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकासवाद के सिद्धांत पर गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए काम करनेवाली एक मजबूत और प्रगतिशील गठबंधन है, वहीं दूसरी और राजद, जद (यू) और कांग्रेस का गठबंधन है जो जंगलराज और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह बिहार की जनता को तय करना है कि बिहार को कहाँ ले जाना है।

उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार आप श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली राजग सरकार को पूर्ण बहुमत दें और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बिहार को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाकर आपको समर्पित करेंगे।

पटना

कमाई, दवाई और पढ़ाई के लिए राज्य के नौजवान पलायन कर रहे हैं

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को बिहार के पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मलेन को सम्बोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए इस बार के बिहार विधान सभा चुनाव में बिहार से भ्रष्टाचार, जंगलराज और कुशासन की सरकार को जड़ से उखाड़ कर राज्य में भाजपा की अगुआई में राजग की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'यह साफ दिख रहा है कि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई में दो तिहाई की बहुमत से राजग सरकार बनाने जा रही है।' उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत ही विभिन्न चुनावों में भाजपा को लगातार विजय श्री प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलनी चाहिए ताकि इसकी धमक देश के कोने-कोने में गूंजे और देश को पता चले कि बिहार की जनता ने बिहार में विकास का परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मन से विकास के प्रतीक श्री नरेन्द्र मोदी को अपना समर्थन दिया है।

कटिहार एवं मुजफ्फरपुर

बिहार में इस बार भाजपा के विकास की सुनामी आ रही है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर को बिहार के कटिहार की रैली और मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता सम्मलेन में विशाल जन-समुदाय को सम्बोधित

किया और इस बार के बिहार विधान सभा चुनाव में जनता से राज्य में दो तिहाई की बहुमत से भाजपा की अगुआई में राजग सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों में जहां राजद, जद (यू) और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है वहीं भाजपा के लिए प्यार और आशीर्वाद और यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस बार बिहार में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है और श्री नरेन्द्र मोदी जी के अगुआई में बिहार में भाजपा-नीत राजग सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार भाजपा के विकास की सुनामी आ रही है।

उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार कहते हैं, राज्य में

विकास करेंगे, राज्य को आगे ले जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 25 वर्षों में आपने बिहार में विकास के लिए क्या किया, आपने बिहार की जनता से विश्वास का धोखा क्यों किया? उन्होंने जनता से पूछा कि क्यों अभी तक राज्य में बुनियादी सुविधाएं भी लोगों तक नहीं पहुँची? श्री शाह ने कहा कि श्री नीतीश कुमार के एक कंधे पर तो जंगलराज के प्रतीक श्री लालू जी हैं वहीं दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का घोटाला करनेवाली कांग्रेस है।

उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार केवल मुखौटा मात्र हैं, उसके पीछे जंगलराज 2 है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि वह फिर से आपसे एक और मौका मांगने आ गए हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जो नीतीश कुमार, दलित के नहीं हुए, जो भाजपा के नहीं हुए, जो बिहार की जनता के नहीं हुए, वो बिहार का विकास कैसे करेंगें। श्री शाह ने कहा कि श्री नीतीश कुमार की राजनीति ही धोखे की राजनीति रही है।

सुपौल

देश के विकास में बिहार के युवाओं का योगदान अतुलनीय है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 अक्टूबर को बिहार के सुपौल में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मलेन को सम्बोधित किया और कार्यकर्ताओं से बिहार में इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की अगुआई वाली दो-तिहाई बहुमत की राजग सरकार बनाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं एकात्म मानववाद की विचारधारा के जरिये देश में विकास का परिवर्तन लाने के लिए बनी पार्टी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के जीत की नींव में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही 10 सदस्यों से शुरू हुई भाजपा आज 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस बार का बिहार चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो बिहार कभी विश्व के एक बड़े भू-भाग पर शासन किया करता था, जो राज्य सम्राट चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चाणक्य की धरती थी, जहां सिकंदर ने भी आकर अपने घुटने टेके थे, जहां पर अर्थशास्त्र और व्याकरण लिखे गए, जो विश्व शिक्षा का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र था, वैशाली गणराज्य के रूप में जिस राज्य ने दुनिया को सबसे पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार दी, आज वह विकास के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने बारी बारी से कांग्रेस, लालू जी और श्री नीतीश कुमार को मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद राज्य विकास में सबसे पीछे है। उन्होंने कहा कि आप एक मौका भाजपा को दीजिये, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम बिहार को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनायेंगे।

पीरपैंती, भागलपुर और रोसड़ा

बिहार की जनता अब विकास चाहती है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 अक्टूबर को बिहार के पीरपैंती, भागलपुर और रोसड़ा के बैजनाथपुर में विशाल जन-समुदाय को सम्बोधित किया और इस बार के बिहार विधान सभा चुनाव में जनता से राज्य में दो तिहाई की बहुमत से भाजपा की अगुआई में राजग सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार इस बार परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री शाह ने कहा कि मूल बात यह है कि श्री नीतीश कुमार खुद को बिहार समझने की भूल कर बैठे हैं और इस बार बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। उन्होंने जनता से सवाल किया कि जिसके एक कंधे पर जंगलराज के प्रतीक श्री लालू जी हों और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का घोटाला करनेवाली कांग्रेस हो, तो वह बिहार में विकास कैसे कर सकते हैं?

उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार एक अहंकारी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की अति महत्त्वाकांक्षा में भाजपा के साथ विकास का गठबंधन तोड़ लिया और फिर से अपने धुर-विरोधी और बिहार को जंगलराज का दंश देनेवाले श्री लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया। श्री शाह ने कहा कि श्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है।

उन्होंने जनता को इनकी चालबाजी से सचेत करते हुए कहा कि श्री नीतीश कुमार केवल मुखौटा हैं, पूरी कवायद तो बिहार में जंगलराज पार्ट-2 की वापसी का है।

श्री शाह ने कांग्रेस, राजद और जद (यू) के शासनकाल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में लगातार इनका शासन रहने के बावजूद आज बिहार बदहाल क्यों है? क्यों आज भी गाँवों तक बिजली नहीं पहुँची है? क्यों अभी भी गाँवों तक सड़कें नहीं पहुँची है? क्यों बिहार की स्वास्थ्य सेवायें बदहाल हैं? क्यों बिहार के युवाओं को पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने पर विवश होना पड़ता है? क्यों बिहार के स्कूली शिक्षा की हालत इतनी दयनीय है?

श्री शाह ने कहा कि श्री नीतीश कुमार, श्री लालू यादव और कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है और उनका विकास का दावा विश्वसनीयता से काफी परे है।

सरायरंजन, परबत्ता, सूर्यगढ़ा और शेखपुरा

नीतीश कुमार केवल मुखौटा हैं, उसके पीछे लालू जी का जंगलराज पार्ट 2 है

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 7 अक्टूबर को बिहार के सरायरंजन, परबत्ता, सूर्यगढ़ा और शेखपुरा की रैलियों में काफी बड़ी तादाद में उमड़े विशाल जनसमुदाय को संबोधित किया और जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर राज्य में दो तिहाई की बहुमत से भाजपा की अगुआई में राजग सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार भाजपा के रूप में बिहार में विकास का परिवर्तन लाने का मन बना लिया है।

श्री लालू यादव के गौ मांस वाले बयान की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे बुरी क्या बात हो सकती है कि गौपालक होते हुए भी लालू जी गाय और बकरे के मांस को एक समान बताते हैं।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और श्री नीतीश कुमार को हर हाल में यह जवाब देना होगा कि वे लालू जी के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? उन्होंने बिहार की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि इन लोगों को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है।

श्री शाह ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, बिजली चाहती है, सुरक्षा चाहती है, विकास चाहती है लेकिन, यह महागठबंधन की सरकार ये सब नहीं दे सकती, केवल भाजपा की अगुआई में राजग की सरकार ही ऐसा कर सकती है। ■

बिहार विधानसभा चुनाव पर एक रिपोर्ट

जंगलराज बनाम विकासराज की लड़ाई

– संवाददाता द्वारा

बिहार विधानसभा चुनाव-प्रचार जोरों पर है। मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच है। राजग गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी शामिल है। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड) एवं कांग्रेस; 'समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा' में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, समरस समाज पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी तथा वामपंथी गठबंधन में भाकपा, माकपा, भाकपा-माले, आरएसपी, फारवर्ड बलॉक और और एसयूसीआईसी शामिल है।

गौरतलब है कि बिहार में 12 अक्तूबर से 5 नवंबर के बीच पांच चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव में विकास मुख्य मुद्दा है। राजग 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देकर चुनाव प्रचार कर रहा है। भाजपा नेता मतदाता से कह रहे हैं कि हम बिहार को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे क्योंकि हमने गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड सहित अनेक राज्यों में विकास की बयार बहाई है। जबकि राजद-जदयू महागठबंधन जातिवाद राजनीति करते हुए बिहार को फिर से पिछड़ेपन में धकेलने का कुचक्र रच रहा है।

बिहार में इस समय करीब पौने छह करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 18 से 30 वर्ष के आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या 1.39 करोड़ है। करीब 13 लाख मतदाता ऐसे हैं जो कि पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जबकि 18 से 21 वर्ष के आयुवर्ग के 50 लाख मतदाताओं में से भी करीब 35 फीसदी मतदाताओं ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। शेष 65 फीसदी मतदाताओं में से ज्यादातर ने बीते साल लोकसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

बिहार में लालूराज जंगलराज का पर्याय था। तब अपहरण उद्योग, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम पर था। बिहार में महागठबंधन सत्ता में आया तो राज्य में जंगलराज-2 की वापसी हो जाएगी। जबकि भाजपानीत शासन में अन्य राज्यों की तरह विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। ■

बिहार : जमीनी हकीकत

प्रति व्यक्ति आय सबसे कम : केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार वर्ष 2013-14 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 15506 रुपए हैं जो सभी राज्यों में सबसे कम है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 39904 रुपए है जिसके मुकाबले बिहार की प्रति व्यक्ति आय आधे से भी कम है। देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की 137401 रुपए है।

साक्षरता दर में सबसे पीछे : जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर मात्र 61.8 प्रतिशत है जो पूरे देश में न्यूनतम है। इस तरह नालंदा और विक्रमशिला की भूमि शिक्षा के मामले में आज देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे निचले पायदान पर है।

व्यापक बेरोजगारी : बिहार की सड़कों पर आज उतने लोग नहीं दिखेंगे जितने दिल्ली या मुंबई की सड़कों पर आपको अनिवासी बिहारी मिल जाएंगे। इसकी वजह यह है कि राज्य में बेरोजगारी के चलते युवाओं को पढ़ाई और रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। नेशनल सेम्पल सर्वे ऑरगेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी 3.8 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

हर तीसरा बिहारी गरीब : तत्कालीन योजना आयोग के अनुसार बिहार में वर्ष 2011-12 में साढ़े तीन करोड़ से अधिक गरीब थे। मतलब, हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। यह हाल तो तब है जब तत्कालीन योजना आयोग ने जुलाई 2013 में बिहार में गरीबों की संख्या करीब 2 करोड़ कम करके बताई है। वास्तव में योजना आयोग ने मार्च 2012 में जो आंकड़े जारी किए थे उनके अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत देश में सर्वाधिक 53.5 प्रतिशत तथा गरीबों की संख्या 5.43 करोड़ थी।

सर्वाधिक कुपोषित बच्चे : केंद्र में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे बिहार में है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार राज्य में मात्र 52 प्रतिशत बच्चे ही सामान्य हैं। जबकि 35 प्रतिशत बच्चे कुपोषण तथा 11 प्रतिशत बच्चे अतिकुपोषण के शिकार हैं। इस तर बिहार में कुपोषित बच्चों की संख्या 19 लाख है जो देश में सर्वाधिक है।

चुनाव सर्वे : राजग को मिल सकता है पूर्ण बहुमत

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टीवी चैनलों द्वारा कराए जा रहे सर्वेक्षणों में राजग गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गयी है। सर्वे के मुताबिक भाजपानीत राजग गठबंधन लगातार अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है जबकि महागठबंधन कमजोर हो रहा है।

जी मीडिया के सर्वे में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले राजग गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गयी है। सर्वे के अनुसार 54 फीसदी मतदाता राजग को वोट करेंगे जबकि 40.2 प्रतिशत मतदाता महागंठबंधन के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। 5.8 प्रतिशत लोग अन्य को चुन सकते हैं. सर्वे के मुताबिक यदि आज मतदान होता है तो राजग 162 सीटें जीतकर सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरेगा जबकि महागंठबंधन को 51 सीटें मिल सकती है।

एबीपी न्यूज-नीलसन के सर्वे के मुताबिक बिहार में राजग गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 128 सीटें मिलने की उम्मीद है यानि स्पष्ट बहुमत की संख्या 122 से 6 सीटें अधिक मिल रही हैं। वहीं राजद-जदयू और कांग्रेस महागठबंधन को 112 सीटें मिलने की उम्मीद है यानि बहुमत से 10 सीटें कम। जबकि अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलने की संभावना है।

दोनों गठबंधनों के बीच 16 सीटों का फासला है जबकि वोट की बात करें तो सिर्फ 2 फीसदी का ही अंतर है. एनडीए गठबंधन को 42 फीसदी, राजग-जदयू-कांग्रेस महागठबंधन को 40 फीसदी और अन्य को 18 फीसदी वोट मिलने की संभावना है। ■

बिहार विधानसभा चुनाव 2015

भाजपा ने जारी किया 'विजन दस्तावेज'

भारतीय जनता पार्टी ने पटना में होने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए विजन दस्तावेज जारी कर दिया है। पार्टी के विजन दस्तावेज को जारी करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने नीतीश कुमार के 'महागठबंधन' की यह कहते हुए आलोचना की कि अब बिहार में 'जंगलराज' समाप्त करने का अवसर आ गया है।

कांग्रेस-जेडी(यू)-आरजेडी के गठबंधन को अवसरवादी की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि 'राजनैतिक स्थिरता' का गुण इस गठबंधन के किसी भी भागीदार में दिखाई नहीं देता है।

उन्होंने कहा कि ये सभी तीन पार्टियां बिहार के लोगों में फेल हो गई हैं। श्री जेटली का कहना है कि 'हमें बिहार को पिछड़ेपन से बचाना है। कांग्रेस, जेडी(यू) और आजेडी ने 68 वर्षों तक राज किया परन्तु वे बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाई। हमारा विजन डाक्युमेंट विकास का चार्टर है।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। हमें इस स्थिति को समाप्त करना होगा।

वित्त मंत्री ने भाजपा के विकास की विश्वसनीयता का उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल था- वहां न सड़कें थी, न बिजली थी, परन्तु भाजपा सरकार ने पिछले पन्द्रह वर्षों में बदल कर रख दिया।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि यदि भाजपा के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस (एनडीए) चुनाव जीतती है और अगली सरकार बनाती है तो अगले पांच वर्षों में विजन डाक्युमेंट में बिहार के विकास की स्पष्ट योजना का प्रावधान है।

बिहार विजन दस्तावेज की विशेषताएं

- प्रत्येक गरीब परिवार के लिए धोती और साड़ी का प्रावधान होगा।
- प्रतिभाशाली कन्या छात्रों को 5000 स्कूटी दी जाएंगी।
- प्रत्येक महादलित और दलित परिवार को नि:शुल्क रंगीन टीवी दिया जाएगा।
- मेडिकल, इंजीनियररिंग, पोलीटेकनीक, आईटीआई कालेजों की स्थापना की जाएगी।
- सन् 2022 तक बेघरों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय और बिजली की व्यवस्था की जाएगी।
- स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ वेंचर पूंजीनिधि की स्थापना होगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी को हैल्थ कार्ड दिया जाएगा।
- प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- परिवार के प्रत्येक मुखिया का दुर्घटना जीवन बीमा किया जाएगा।
- भूमिहीन व्यक्तियों 5 डेसीमल भूमि दी जाएगी।
- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 5000 लैपटाप दिए जाएंगे।
- कृषि के लिए विशेष बजट नियत किया जाएगा।
- अगले एक वर्ष में प्रत्येक गांव में बिजली का प्रावधान होगा।
- नई कृषि विश्वविद्यालय तथा पशुविद्यालय खोले जाएंगे।
- भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सतर्कता अदालतें खोली जाएंगी।
- पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कोचि हबों का विकास किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए चौबीस घण्टे नियंत्रण कक्ष खुला रहेगा।
- किसानों को कम से कम 12 घण्टे बिजली दी जाएगी।

कालेधन के विरुद्ध राजग सरकार का अभियान

– अरुण जेटली

कोई भी समाज ऐसे तंत्र को अनिश्चितकाल तक बनाए नहीं रख सकता जहां कमाई करने वाले व्यक्ति कर चोरी को जीवन का एक तरीका समझें। दुर्भाग्य से विगत में हमारे यहां टैक्स की दर काफी अधिक होने के चलते कर चोरी को प्रोत्साहन मिला। देश जब अपने नागरिकों पर तर्कसंगत दर से टैक्स लगाते हैं तो वे उन्हें ईमानदारी से उनकी आय का खुलासा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में भारत में टैक्स की काफी अधिक दर रही जिसके चलते लोगों ने कर चोरी की। उस समय सरकार की इतनी क्षमता भी नहीं थी कि इस कर चोरी को पकड़ा जा सके। इसके बाद भारत ने धीरे-धीरे टैक्स की दरें कम करने की दिशा में कदम उठाना शुरु कर दिया। राजग सरकार की सोची समझी रणनीति रही है कि राजकोषीय नीति के माध्यम से कर छूट की सीमा बढ़ाकर तथा बचत को प्रोत्साहित कर मध्य और निम्न आय वर्ग के लोगों की जेब में अधिक पैसा रखा जाए। इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा तथा अर्थतंत्र में अधिक धन का प्रवाह होगा। उपभोग से अप्रत्यक्ष करों की राशि बढ़ती है। भारत को निवेश अनुकूल राष्ट्र बनाने के लिए मैंने आम बजट 2015 में निगम कर को अगले चार वर्ष में चरणबद्ध तरीके से घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की घोषणा की थी। इसके साथ इस अवधि में कार्पोरेट को प्राप्त छूटों को भी चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार अपने इस रुख पर कायम है।

सरकार की नीति कर संरचना को तर्कसंगत बनाने, तर्कसंगत दर पर टैक्स वसूलने, निम्न आय वर्ग के लोगों के हाथ में अधिक धनराशि छोड़ने और समाज के सभी वर्गों में प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की है। इससे उन लोगों के नकेल कसने में मदद मिलेगी जो कालेधन का इस्तेमाल करते हैं।

विदेश में जमा कालेधन के खिलाफ अभियान

सरकार ने कालेधन की समस्याएं के निदान के लिए सोच-समझकर एक रणनीति तैयार की है। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दो रिटायर न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जो कालेधन के विरुद्ध समग्र प्रयासों की निगरानी करेगा। संप्रग सरकार कोई न कोई बहाना कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में तीन साल तक टालमटोल करती रही थी। सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जेनेवा के एचएसबीसी और लीचेस्टीकन बैंक में धनराशि जमा करने वाले लोगों के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध थी उसके आधार पर आयकर का आकलन किया। अधिकांश मामलों में आकलन पूरा कर लिया गया है और जहां भी गैर कानूनी गतिविधियां पाई गई हैं उन मामलों में ऐसे खाताधारकों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन चलाया जा रहा है। इन सभी खातों में 6500 करोड़ रुपये बेलेंस पाया गया है। यही वजह है कि सरकार ने देश से बाहर विदेश में अघोषित संपत्ति को कर के दायरे में लाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव किया। क्योंकि यह टैक्स पहली बार लगाया गया इसलिए जो लोग अपनी गैर कानूनी संपत्ति का खुलासा करना चाहते थे उनके लिए 90 दिन की एक कंप्लायंस विंडो (पालन समयावधि) दी गई। इस अवधि में उन्हें अपनी विदेशों में जमा अघोषित संपत्ति का खुलासा करना था। यह अवधि 30 सितंबर 2015 को खत्म हो गई। विदेशों में अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं को को 30 प्रतिशत टैक्स तथा 30 प्रतिशत की दर से जुर्माना 31 दिसंबर 2015 से पहले जमा करना है। जिन लोगों ने इस निर्धारित अवधि में अपनी विदेशों में जमा अघोषित संपत्ति का खुलासा किया है उन पर नए कानून के तहत मुकदमा नहीं चलेगा। 638 लोगों ने अपनी 3770 करोड़ रुपये आय का खुलासा किया है। इस संपत्ति का खुलासा करने वाले अब चैन की नींद सो सकते हैं। जिन लोगों ने विदेश में सपत्ति जमा कर रखी है लेकिन उन्होंने इस अवधि के भीतर इसका खुलासा नहीं किया है उन लोगों पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स तथा 90 प्रतिशत जुर्माना देगा होगा। इस तरह ऐसे लोगों की पूरी संपत्ति जमा करने के साथ ही उनसे और अधिक धनराशि वसूली

जाएगी। इसके अलावा उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा जिसमें उन्हें दस साल तक की सजा हो सकेगी। इस तरह यह कानून भविष्य में भारत से पैसा बाहर जाने से रोकेगा।

एचएसबीसी में 6500 करोड़ रुपये तथा निर्धारित समयावधि में घोषित विदेशी संपत्ति 3770 करोड़ रुपये को किसी भी कर माफी योजना के तहत आय नहीं समझा जाना चाहिए। इस धनराशि की तुलना घरेलू कालेधन माफी की योजना से करना अनुचित है। घरेलू कालेधन के खिलाफ सरकार अलग से कदम उठा रही है।

कर चोरी रोकने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने जी-20 की बैठक में पहल करके एक देश के नागरिक द्वारा गैर कानूनी तरीके से विदेश में पैसा जमा के मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया। जी-20 की इस पहल का मकसद बैंकिंग लेन-देन से गोपनीयता का पर्दा हटाना तथा किसी भी देश को उसके नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के बारे में उस देश की सरकार को रीएल टाइम में सूचित करना है। सरकार ने फटका के तहत अमेरिका के साथ एक करार किया है जिसमें भारत और अमेरिका एक दूसरे के नागरिकों के विदेशी वित्तीय संस्थाओं में खाते से लेन-देन के बारे में रीएल टाइम में एक दूसरे को सूचित करेंगे। यह सहयोग उन सभी देशों के साथ भी होगा जो जी-20 के अधिकार क्षेत्र के तहत सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के वैश्विक मानकों पर हस्ताक्षर करेंगे। राजस्व सचिव के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों के एक दल ने स्विस अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की थी। मंत्री स्तर पर भी वार्ताएं की गई हैं। स्विटजरलैंड भारत को एचएसबीसी के उन खातों के बारे में जानकारी देने को तैयार हो गया है जिनसे जुड़ी हुई सूचनाएं भारत चुराई गई जानकारी के अतिरिक्त भी वहां की सरकार को देगा। गौरतलब है कि एसएचबीसी खातों के बारे में चुराई गई सूचना फ्रांस के माध्येम से भारत सरकार को मिली थी।

ऐसे में उम्मीद है कि आगामी दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रुपरेखा तैयार हो जाएगी और कुछ शर्तों के साथ विदेशों में जमा कालेधन के के बारे में जानकारी मांगने वाले देशों को सूचनाएं मिलनी लगेंगी। इस तरह जिन लोगों ने विदेश में कालाधन जमा किया है जब उनके बारे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सूचनाएं भारत के कर प्रशासन के पास पहुंच जाएगी।

घरेलू काला धन

अधिकांश कालाधन अब भी भारत में ही जमा है। इसलिए हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है ताकि प्लास्टिक करंसी को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए तथा नकदी से लेन देन को कम किया जाए। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्राधिकारों के साथ काम कर रही है ताकि इस बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सके। बड़ी संख्यान में पेमेंट गेटवे के खुलने, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट बैंक और ई-कारोबार के उभरने से बैंकिंग लेन-देन बढ़ेंगे तथा प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। इस दिशा में जैम (जनधन, आधार और मोबाइल) तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजने के लिए डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसी दिशा में प्रयासों को मजबूती देगा। जन धन योजना के सभी 18 करोड़ खाताधारकों को रुपे कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। इससे उन्हें प्लास्टिक मनी से परिचित होने और इसके इस्तेमाल करने को बढ़ावा मिलेगा। मुद्रा योजना ने अगले कुछ वर्षों में भारत के 25 करोड़ परिवारों में से छह करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। बैंक उन लोगों को जो लोन देंगे उसे सिर्फ मुद्रा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एटीएम से निकाला जा सकता है। इस तरह उनके अधिकांश लेन देन प्लास्टिक करंसी या बैंकिंग तंत्र के माध्यम से होंगे।

सरकार एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी का लेन-देने होने पर पैन कार्ड का ब्यौरा देने के लिए नियम बनाने जा रही है। आयकर के निगरानी तंत्र को मजबूत बनाते हुए कर चोरी के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से पता लगाने के लिए क्षमता बढ़ाई गई है। नकदी के बड़े लेन-देन का पता लगाने के लिए इसकी क्षमता मजबूत की जा रही है। जीएसटी लागू होने पर भी इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रकार सोने जैसी वस्तुएं जहां निर्यातक कस्टम ड्यूटी के भुगतान के बाद खरीदता है उसके बाद के जो भी ट्राजेंक्शन नकदी से होंगे उन्हें आसानी पकड़ा जा सकता है।

सरकार की नीति कर संरचना को तर्कसंगत बनाने, तर्कसंगत दर पर टैक्स वसूलने, निम्न आय वर्ग के लोगों के हाथ में अधिक धनराशि छोड़ने और समाज के सभी वर्गों में प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की है। इससे उन लोगों के नकेल कसने में मदद मिलेगी जो कालेधन का इस्तेमाल करते हैं। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं।)

प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा

21वीं सदी, भारत की सदी : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 23 सितंबर से शुरू हुई 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा बेहद सफल रही। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, बल्कि विश्व के तमाम प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की। इस दौरे पर श्री मोदी ने दुनिया की दिग्गज कम्पनियो के सीईओ से मुलाकात कर भारत में निवेश को लेकर चर्चा की। गूगल कम्पनी के सीईओ श्री सुंदर पिचई ने 500 रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट मुहैया कराने का आश्वासन दिया। श्री मोदी के साथ फेसबुक के संस्थापक श्री मार्क जुकरबर्ग ने प्रभावी संवाद किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कैलिफोर्निया स्थित सिलिकान वैली में भारतीय समुदाय के करीब 18,500 लोगों को संबोधित भी किया।

वित्तीय क्षेत्र के दिग्गज सीईओ से मिले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितंबर की शाम को न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां पर उन्होंने वित्तीय क्षेत्र पर गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जे पी मोरगन के चेयरमैन, सीईओ और अध्यक्ष श्री जैमी डीमोन, ब्लैक स्टोन के

चेयरमैन, सीईओ और सह-संस्थापक श्री स्टीव श्वार्जमैन, टाइगर ग्लोबल के सह-संस्थापक और प्रबंधकीय साझेदार चेज कोलमैन, न्यूयॉर्क स्टेट कॉमन रिटायरमेंट फंड के मुख्य निवेश अधिकारी श्री विक्की फूलर आदि उपस्थित थे।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने ''स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया'' की परिकल्पना रखी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ ही वे निजी शुरूआत और उद्यमिता पर जोर दे रहे हैं, जिसका उल्लेख वे 'व्यक्तिगत क्षेत्र' के रूप में करते हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप और नवाचार, सूचना तकनीकी क्रांति के केन्द्र रहे हैं।

मीडिया, प्रौद्योगिकी और संचार पर गोलमेल बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के सर्वोच्च अमरीकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में न्यूज कारपोरेशन और 21 सेंचुरी फॉक्स के एक्जक्यूटिव चेयरमैन श्री रूपर्ट मर्डोक, 21 सेंचुरी फॉक्स के सीईओ श्री जेम्स मर्डोक, न्यूज कारपोरेशन के सीईओ श्री रॉबर्ट थॉमसन, स्टार

इंडिया के सीईओ श्री उदय शंकर, डिस्कवरी कम्युनिकेशन्स के अध्यक्ष और सीईओ श्री डेविड जासलेव, सोनी इंटरनेंटमेंट के सीईओ श्री माइकल लिंटन आदि शामिल थे।

प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने पाया कि हाल के दिनों में प्रौद्योगिकी और मीडिया में परिवर्तन से ज्ञान तेजी से आम लोगों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अब प्रौद्योगिकी-चालित युग में है। उन्होंने अपील की कि भारत में निवेश योजनाएं तैयार करते समय वे क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखें। उन्होंने 600,000 गांवों को ब्रॉडबैंड

कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ने की अपनी सरकार की परिकल्पना के बारे में बताया।

प्रधानमंत्री की प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपनी पिछली बैठक से अब तक द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भूमि सीमा समझौते के कार्यान्वयन में प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री डॉ. राल्फ गोंजाल्विस से भेंट की। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क शहर में भूटान, श्रीलंका, स्वीडन और साइप्रस के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भूटान में पनबिजली परियोजनाओं में हो रही प्रगति की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात की। उन्होंने इस वर्ष श्रीलंका में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए दो चुनावों के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति को बधाई देते हुए कहा कि यह आपके देश में लोकतंत्र की परंपराओं की गहरी जड़ों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन लोफवेन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस एनस्टेसिएडेस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने साइप्रस के साथ लंबे समय से चल रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि दोनों देश प्राकृतिक रूप से एक-दूसरे से दूर हैं लेकिन वे भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के बहुत नजदीक हैं।

कैलिफोर्निया से लौटने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूयॉर्क शहर में अमरीका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा से मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसियो होलांद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान चार समान विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, चार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की सदस्यता पाने की भारत की इच्छा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार शामिल रहे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री मोदी और जुकरबर्ग के संवाद की मुख्य बातें

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को अमेरिका के सिलिकन वैली स्थित फेसबुक के मुख्यालय पहुंचे। वहां फेसबुक के सीईओ श्री मार्क जुकरबर्ग ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि दोनों ने टाउनहॉल में लोगों के सवालों के जवाब भी दिए।-

- आज सोशल मीडिया से गलत करने से लोग डरते हैं। अब सोशल मीडिया लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है। सभी सरकारों को इससे जुड़ना चाहिए।
- अच्छी सरकारें तब चलती हैं जब आपके पास रियलटाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम हो। आज तुरंत लोगों से जवाब मिल जाता है। तुरंत सूचना मिल जाती है। रियलटाइम सूचना के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा साधन है।
- मेक इन इंडिया की सफलता का रहस्य यह है कि दुनिया की कोई कंपनी बंद नहीं होना चाहती। भारत में लो कॉस्ट मैनुफैक्चरिंग है। भारत में बाजार भी है, इसलिए यह कामयाब होगा।
- दुनिया में भगवान की कल्पना सभी समाजों में है, लेकिन हर समाज में भगवान पुरुष ही हैं। अकेले भारत में स्त्री भगवान की कल्पना की गई है। हमारी संस्कृति में नारी के इस रूप की कल्पना की गई है।
- दुनिया में कई जगहों में महिलाओं को चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन भारत में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है। संसद में भी भागीदारी के लिए आरक्षण के लिए बहस जारी है ताकि निर्णय प्रक्रिया में भी महिला की भागीदारी हो।

21वीं सदी हिन्दुस्तान की सदी

27 सितंबर को सैन जोस के सैप सेंटर में भारतीय समुदाय के करीब 18,500 लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20-25 वर्षों से यह चर्चा चल

रही थी कि 21वीं सदी किसकी होगी, हर कोई यह तो जरूर मानता था कि 21वीं सदी एशिया की होगी लेकिन पिछले कुछ समय से लोग ये मानने लगे हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं, बल्कि 21वीं सदी हिन्दुस्तान की सदी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद में अच्छे या बुरे के आधार पर भेदभाव की धारणा को गलत करार देते हुए कहा कि आतंकवाद हमेशा बुरा होता है। इसे अच्छे आतंकवाद या बुरे आतंकवाद की श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता। सैप सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र जल्द ही इस बारे में निर्णय लेगा कि आतंकवाद से किस प्रकार निपटा जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 'जेएएम' पहल पर जोर दिया, जिसमें जन धन योजना के तहत बैंक खातों को आधार कार्ड और मोबाइल गवर्नेंस से जोड़ा जाना शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सैप सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के बीच सप्ताह में तीन दिन इस साल दो दिसंबर से सीधी उड़ान सेवा की घोषणा की।

उत्साहित भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दो दिसंबर से एयर इंडिया सप्ताह में तीन दिन दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान सेवा का संचालन करेगी।

भारत-अमेरिकी संबंधः सहयोग व विश्वास का बढ़ता दायरा

अमरीकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व आज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है और जो वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं, इनके बीच हमारी भागीदारी, हमारे लिए और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्रकृति के संरक्षण सहित सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम नवाचार और प्रौद्योगिकी लागू कर सकते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में, हमारे उपायों में सिर्फ वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने की योजना ही शामिल नहीं है, बल्कि विकास की रणनीति भी शामिल है जो हमें ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा सम्मिश्रण के प्रति परिवर्तन में सक्षम बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी विलक्षण द्विपक्षीय भागीदारी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा की दक्षता पर केंद्रित है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा व्यापार और प्रशिक्षण सहित हमारे रक्षा सहयोग का दायरा व्यापक हो रहा है। मौजूदा आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है और नया आतंकवाद पनप रहा है, ऐसे में हमें आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ने के लिए अपना सहयोग और बढ़ाना होगा। हमने हाल ही में साइबर सुरक्षा संवाद को सफलतापूर्वक संपन्न किया है।

शेष पृष्ठ 30 पर

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 60 साल बाद आयरलैंड की यात्रा

आतंकवाद, कट्टरता सहित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर 2015 को आयरलैंड की यात्रा की तथा आयरलैंड के प्रधानमंत्री श्री एंडा केनी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी को आयरलैंड क्रिकेट टीम की जर्सी और एक ''हर्लिंग किट'' उपहार के रूप में दिया। हर्लिंग आयरलैंड के प्रमुख खेलों में से एक है। आरंभिक वक्तव्य में दोनों नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय प्रधानमंत्री करीब 60 साल बाद आयरलैंड की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान मोदी ने दोनों देशों के बीच साझा किए गए मूल्यों का उल्लेख किया।

आतंकवाद, कट्टरता सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और यूरोप एवं एशिया की परिस्थितियों के बारे में दोनों तरफ से व्यापक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने तय समय सीमा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधारों के लिए आयरलैंड से समर्थन की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत की सदस्यता के लिए भी आयरलैंड से समर्थन देने की मांग की।

आतंकवाद, कट्टरता सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और यूरोप एवं एशिया की परिस्थितियों के बारे में दोनों तरफ से व्यापक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने तय समय सीमा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधारों के लिए आयरलैंड से समर्थन की मांग की।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने आयरलैंड में बसे भारतीय समुदाय से मुलाकात की। आयरलैंड में संस्कृति की शिक्षा देने वाले वहां के एक स्थानीय स्कूल, जॉन स्कॉटिश स्कूल में पढ़ने वाले 20 आयरलैंड के छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में संस्कृत के श्लोकों का गान किया।

प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से हो रहे बदलावों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत, दुनियाभर में सबसे तेजी से उभरने और विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि दुनिया को पहले ही इस बात का आभास हो चुका है कि 21वीं सदी पूर्ण रूप से एशियाई देशों की सदी होगी, जिसमें एशियाई देशों का ही बोलबाला होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वर्तमान विकास दर यदि आने वाले 30 सालों तक ऐसे ही बनी रही, तो देश से गरीबी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 65 फीसदी लोग 35 वर्ष की आयु से कम हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दुनिया का सबसे युवा देश, विकास की गति को बनाए रखने और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। ■

महत्वपूर्ण 18 समझौतों पर हस्ताक्षर
सौर परियोजनाओं के लिए एक अरब यूरो की मदद की घोषणा

जर्मनी की चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल की 5-6 अक्टूबर की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान 18 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी ने भारत की सौर परियोजनाओं के लिए एक अरब यूरो की मदद की घोषणा की। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, बौद्धिक, रेलवे, व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई और आतंकवाद के खतरे से मिलकर लड़ने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के बीच 5 अक्टूबर को हुयी वार्ता के बाद रणनीतिक क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए दोनों पक्षों ने 18 सहमति-पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। इनमें भारत में जर्मन कंपनियों के लिए तेजी से मंजूरी दिलाने और जर्मनी द्वारा एक अरब यूरो के सौर ऊर्जा कोष की घोषणा भी शामिल हैं। श्री मोदी और सुश्री मर्केल ने तीसरी शिखरवार्ता स्तर के अंतर-सरकारी परामर्श की सह-अध्यक्षता करते हुए रक्षा, सुरक्षा, खुफिया जानकारी, रेलवे, व्यापार और निवेश और स्वच्छ ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने पर सहमति जताई और आतंकवाद के खतरे से मिलकर लड़ने का फैसला किया।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि हमारा ध्यान आर्थिक संबंधों पर है, लेकिन मेरा मानना है कि असीमित चुनौतियों और अवसरों के संसार में भारत और जर्मनी दुनिया के लिए और अधिक मानवीय, शांतिपूर्ण, न्यायोचित तथा टिकाउ भविष्य हासिल करने में भी मजबूत साझेदार हो सकते हैं। जर्मनी की कंपनियों के लिए फास्ट-ट्रैक मंजूरी प्रक्रिया पर समझौते में अनेक परियोजनाओं के लिए एकल बिंदु स्वीकृति शामिल है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक जर्मन कंपनियों को मोदी की महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' पहल से जोड़ने और महत्वपूर्ण तरीके से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन, आधुनिक प्रौद्योगिकी में व्यापार, खुफिया जानकारी और आतंकवाद तथा उग्रवाद का मुकाबला करने के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी। ये हमारे विस्तृत होते रिश्ते के महत्वपूर्ण सुरक्षा आयाम हैं। जर्मनी ने बातचीत में भारत की सौर परियोजनाओं के लिए एक अरब यूरो की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। जर्मन भाषा को भारत में एक विदेशी भाषा के तौर पर और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जर्मनी में प्रचार के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय के बीच एक संयुक्त सहमति घोषणापत्र पर दस्तखत भी किये गये जो 5 अक्टूबर को हुए 18 समझौतों में शामिल है।

दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। श्री मोदी और सुश्री मर्केल ने आतंकवाद और उग्रवाद के बढ़ते खतरे और इनकी वैश्विक पहुंच को लेकर अपनी चिंता साझा की तथा इन चुनौतियों से निपटने के मकसद से सामूहिक सहयोग के लिए सहमत हुए। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद निरोधक कार्रवाई पर संयुक्त कार्यसमूह की बैठकें आयोजित करने का फैसला किया। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि जर्मनी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार समझौते जैसी अनेक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के साथ भारत के तेज होते सहयोग का स्वागत करता है।

दोनों पक्षों ने इन व्यवस्थाओं में पूर्ण सदस्य के तौर पर भारत को शामिल किये जाने और इस तरह वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रयासों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहने की रजामंदी जताई।

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर से जुड़ी 10वीं सदी की महिषासुर मर्दिनी अवतार वाली दुर्गा प्रतिमा को लौटाने के लिए भी मर्केल और जर्मनी की जनता का शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं ने अनेक क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विषयों पर मंथन किया और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की आजादी के महत्व को और अंतरराष्ट्रीय कानून के स्वीकार्य सिद्धांत के अनुरूप गुजरने के अधिकार तथा अन्य समुद्री अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया।

जर्मनी की ओर से भारत में व्यापार करने को सुगम बनाने की मोदी की प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया।

व्यापक परिणामों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम निर्माण, बुनियादी संरचना और कौशल विकास में निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी की बढ़ती साझेदारियों को लेकर विश्वास के साथ आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि जर्मन का इंजीनियरिंग कौशल और भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कौशल अगली पीढ़ी के ऐसे उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं जो अधिक सक्षम, किफायती तथा पर्यावरण हितैषी होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में 1600 जर्मन कंपनियां और इनकी बढ़ती संख्या देश में वैश्विक कार्यबल का निर्माण करने में मजबूत साझेदार होंगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी, स्वच्छ गंगा और कचरा प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में जर्मनी के सहयोग और सहायता ने ठोस आकार लिया है। सुश्री मर्केल ने बातचीत के परिणामों पर संतोष जताया और अनेक परियोजनाओं पर काम करने की मोदी की 'गति' की प्रशंसा की। सुश्री मर्केल ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्रों समेत अनेक मुद्दों पर दोनों देशों की विभिन्न पहलों को भी गिनाया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की निंदा की। उन्होंने सीरिया में आतंकवाद से सफलतापूर्वक लड़ने और वहां हिंसा को नेस्तानाबूद करने के लिए उस देश में राजनीतिक समाधान की वकालत की, वहीं इराक में राष्ट्रीय सुलह और एकता के महत्व को रेखांकित किया।

दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते खाद्य सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास तथा वाणिज्यिक शिक्षा, निर्माण, नागरिक उड्डयन, आपदा प्रबंधन और कृषि के क्षेत्रों में सहयोग के लिए किये गये। खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा जर्मनी के फेडरल ऑफिसर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फूड सेटी के बीच एक संयुक्त आशय घोषणापत्र पर दस्तखत किये गये।

श्री मोदी और सुश्री मर्केल ने सभी देशों की संप्रभु समानता और उनकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान को बरकरार रखने के लिए मजबूत समर्थन जताया।

उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में अशांति का कूटनीतिक समाधान तलाशने के प्रयासों को पूरा समर्थन व्यक्त किया। दोनों ने इस साल पेरिस में होने वाले जलवायु सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी, व्यापक और संगत जलवायु समझौते पर पहुंचने के लिए फ्रांस को पूरा समर्थन व्यक्त किया। ■

एंजेला मर्केल की यात्रा 'सार्थक' रही : नरेन्द्र मोदी

जर्मनी की चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मन नेता की यात्रा 'सार्थक' रही है और इससे भारत-जर्मनी संबंध 'नई ऊंचाइयों' पर पहुंचे हैं। सुश्री मर्केल की दो दिवसीय यात्रा पूरी होने के बाद मोदी ने ट्वीट किया, 'वह भारत से रवाना हुई, चांसलर मर्केल का आभार। यह सार्थक यात्रा रही है जिसने भारत-जर्मनी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।'

प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्केल का बेंगलुरू दौरा

भारत निवेश के लिए एक बेहतरीन स्थान : मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 अक्टूबर बेंगलुरू का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरू में बुश इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन में जर्मनी की चांसलर सुश्री एंजेला मार्केल की अगवानी की। दोनों नेताओं के समक्ष नेत्र रोग और दुर्घटना पीड़ितों को फौरन सहायता पहुंचाने संबंधी सेवाओं के बारे में बुश इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन द्वारा विकसित प्रणालियों को प्रस्तुत किया गया। बुश वोकेशनल सेंटर में दोनों नेताओं को स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्तियों के कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों का परिचय दिया गया।

प्रधानमंत्री और जर्मनी की चांसलर ने नेस्कॉम और फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक व्यापार सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी के दौर में भारत निवेश के लिए एक बेहतरीन स्थान है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों संबंधी तमाम लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी। उन्होंने भारत में मौजूद निवेश के विभिन्न अवसरों के बारे में भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे द्वारा त्वरित डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों के जरिये इस व्यापक संभावना को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऊर्जा का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए हमने स्टार्ट अप इंडिया अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सॉफ्टवेयर ही पूरी दुनिया में हार्डवेयर को गति प्रदान करेंगे। भारत की प्रतिभा ही प्रौद्योगिकी में पारंगत साबित होगी और भारत के बाजार ही विनिर्माण क्षेत्र को प्रेरित करेंगे। अत: भारत में व्यवसाय करना फायदे का सौदा साबित होगा। 'मेक इन इंडिया' के लिहाज से तो यहां व्यवसाय करना और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी ट्वीट में कहा, ''मैं चांसलर मर्केल के विजन की सराहना करता हूं जिसके तहत जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मिलकर विश्व स्तरीय उत्पादों का सृजन की दिशा में अग्रसर रहे। चांसलर मर्केल भारत से विदा हो रही हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनका भारत दौरा बहुत सकारात्मक रहा और भारत-जर्मनी संबंधों को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई।'' ■

पृष्ठ 26 का शेष...

नवीकरणीय ऊर्जा पर गोलमेज बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेन जोस में शीर्ष ऊर्जा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीइओ) और विशेषज्ञों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ऊर्जा सचिव डॉ. अर्नेस्ट मोनिज और भूतपूर्व अमेरिकी ऊर्जा सचिव प्रोफेसर स्टीवन चू भी इस बैठक में उपस्थित थे। गोलमेज बैठक में व्यक्त किये गए विचारों से यह स्पष्ट अभिकथन सामने आया कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दुनिया की राजधानी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रतिभागियों ने कहा कि बिजली का भंडारण सस्ता होने से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा जल्दी ही एक सस्ता विकल्प बन जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत का सर्वाधिक योगदान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित शांति स्थापना के अभियानों से संबंधित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 180,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने भाग लिया है, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। भारत ने अब तक 69 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 48 में हिस्सा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में भाग लेते हुए 161 भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस अवसर श्री मोदी ने कहा कि भारत पहला देश है, जिसने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान अपनी महिला फॉर्मड पुलिस यूनिट को भेजा। भारत बड़ी तादाद में देशों के शांति रक्षक अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता आया है। अब तक, 82 देशों के करीब 800 अधिकारियों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति रक्षा अभियान विवेकपूर्ण तरीके से, अपनी सीमाओं को पूरी तरह समझते हुए और राजनीतिक समाधानों की सहायता से संचालित किए जाने चाहिए। हमें खुशी है कि शांति अभियानों पर उच्च स्तरीय स्वतंत्र पैनल ने इन विषयों की पहचान की है। पैनल की सिफारिशों पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र महासचिव का आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके जल्द विचार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ■